

आज

बेबाक

संसद प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। शायद यही वजह है कि वहां बहुत बड़े वाले लोग ही पहुंचते हैं। जो बड़े लोगों की ही बातें करते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आम आदमी की गरीबी और बेरोजगारी जैसी तुच्छ बातों पर बहा संसद का कीमती वक्त जाया नहीं किया जाता। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नृरा कुश्ती चल रही है। बकौल धूमिल- एक आदमी रोटी खाता, दूसरा आदमी रोटी बेलता एक और आदमी है जो रोटी से खेलता है, ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है।

खास खबर

पटोले निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष

मुंबई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले को रविवार को निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने उम्मीदवार किशन कठोरे का नामांकन वापस ले लिया था। छप्पन वर्षीय श्री पटोले शिव सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में एमबीए की अगुवाई में उद्धव ठाकरे की सरकार ने शनिवार को विधानसभा में आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया। श्री पटोले चार बार विधायक रह चुके हैं और वह विदर्भ की सकाली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दंड से नहीं अपराध बोध से घटेगा नारियों पर अत्याचार : शंकराचार्य

नरसिंहपुर। हैदराबाद में घटित घटना की निंदा करते हुए ज्योतिष एवं द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि देश में नारी के प्रति सम्मान करने की शिक्षा आने वाली पीढ़ी को नहीं दी जा रही है, इसी के कारण ऐसे अपराधों में इजाफा हो रहा है। शंकराचार्य ने आज मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित अपने आश्रम झोतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में मौड़िया से चर्चा में कहा कि नारियों के प्रति अपराध करने वाले को दंड देने से नहीं, अपराध करने वाले में अपराध बोध से नारियों पर होने वाला अत्याचार घटेगा। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाला साक्ष्य मिटाने का प्रयास करता है, वह सोचता है कि उसके अपराध को कोई नहीं देख रहा जबकि उसके अपराध को हजारों आंखों वाला भगवान देखता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को नारी के प्रति सम्मान की जो भावनाएं धर्म शास्त्रों में अंकित है, उसकी शिक्षा देना आवश्यक है।

गरमा-गरमा

श्रम नहीं रहे दुकानें : ग्रीष्मकाल में नगरपालिका के माध्यम से

हम तो इसकी निंदा ही कर सकते हैं...

आईएएस एसोसिएशन अध्यक्ष की मनमानी भी बर्दाश्त नहीं प्रदेश सरकार के निशाने पर निरंकुश ब्यूरोक्रेट्स!

- अन्य चार आईएएस भी सरकार के टारगेट पर
- सक्रियता और योग्यता ही होगी प्राथमिकता

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के परिवर्तन से यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि वर्तमान सरकार किसी भी कीमत पर अब



- दागदार, निरंकुश अफसरों की तरफदारी पड़ी भारी
- विवादित अफसरों की फील्ड पोस्टिंग की भी होगी जांच

ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी को बर्दाश्त करने के मूड़ में नहीं है। आधे से अधिक मंत्री अपने प्रमुख सचिवों को उनकी मनमानी के चलते अपने कार्य में असहजता

महसूस कर रहे हैं और इसकी पीड़ा वह अनेकों बार मुख्यमंत्री कमलनाथ को व्यक्त भी कर चुके हैं। जिसमें एक खेमे विशेष के तो लगभग सभी मंत्री इस पीड़ा से गुजर रहे हैं लेकिन हाल ही के परिवर्तन में आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग का जिस तरह से परिवर्तन कर हाशिए पर डाला गया है, उसने सभी को चौंका भी दिया है। साथ ही सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि तेज तर्रार, सक्रिय आईएएस को सरकार की प्राथमिकता वाले विभागों में प्रमुखता से पदस्थ किया जाएगा। इसके लिए पिछली सरकार के कार्यकाल की कार्य परिणीति, परिणाम को

भी ध्यान में रखते हुए पदस्थापना पर विचार किया जाएगा। पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां अपनी कार्यशैली के लिए विवादास्पद और चर्चित आईएएस को जो कि प्रदेश से बाहर हैं उनकी तरफदारी भी एसोसिएशन की अध्यक्ष को भारी पड़ी।

वहीं दूसरी ओर अपनी सक्रियता और योग्यता के लिए चर्चित अधिकारी को पिछली सरकार द्वारा अचानक ही महत्वहीन विभाग में पदस्थ करने के पीछे भी पिछले सरकार के मुहलगे आईएएस कॉकस का ही हाथ माना जा रहा था। वर्तमान सरकार अब पिछली सरकार के पक्षपात को भी शेष पृष्ठ 7 पर

टेंडर घोटाले की चर्चा में आये 2 आईएएस

अभी हाल ही में टेंडर घोटाले की प्रक्रिया में चर्चा में आए दो आईएएस के सुपुत्रों से जुड़ी कंपनियों की कारगुजारियों की भी परतें खोलने के मूड़ में सरकार जंगर आ रही है। क्योंकि निर्माण विभागों के नैब्युअल जो कि कैबिनेट से अनुमोदित होते हैं उनमें बाद में कैबिनेट के बगैर किसी भी कंपनी या व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से परिवर्तन या संशोधन करना या करवाना एक गंभीर अपराध है और ऐसी स्थिति में इन मामलों से जुड़े या अन्य किसी भी मामले में एसोसिएशन की अध्यक्ष द्वारा विवादित आईएएस की तरफदारी भी उनको भारी पड़ गई। जिसको सरकार ने गंभीरता से लिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पर ग्रामीण विकास विभाग के दागदार, विवादित अफसरों की पदस्थापना को भी गंभीरता से लिया है। विभाग में निर्विवाद रूप से उपलब्ध अधिकारियों की लंबी श्रृंखला के बाद भी विवादित अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग भी विभाग में चर्चा का विषय है।

शिक्षा में संस्कार, देशभक्ति और पर्यावरण का एहसास होना जरूरी - मंत्री पटवारी

नालंदा और तक्षशिला की शिक्षण संस्कृति को अपनाएं विश्वविद्यालय - राज्यपाल

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज इंदौर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी और यूनिवर्सिटी के संस्थापक, पद्मभूषण डॉ. एस.बी. मजूमदार दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल टंडन ने कहा कि जब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, तब हमें शिक्षा के अपने पुरातन इतिहास को याद करना होगा, जिसके दम पर दुनिया हमें विश्व-गुरु मानती थी। उन्होंने कहा कि विध्वंसकारी शक्तियों द्वारा समय के साथ हमारी शिक्षा क्षीय को भी लूटा गया, साहित्य को जलाया गया। इन सब के बावजूद हमारे विद्वानों ने श्रुति और स्मृति के आधार पर शैक्षणिक इतिहास और साहित्य को बार-बार पुनर्जीवित किया। राज्यपाल ने कहा कि हमें पुरातन शिक्षण व्यवस्था की नींव पर नए भारत की इमारत खड़ी करनी होगी। लालजी टंडन ने कहा कि भारत को पुनः विश्वगुरु का दर्जा दिलाने के लिए विश्वविद्यालयों



को नालंदा और तक्षशिला की शिक्षण प्रणाली को अपनाना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि हमें विद्यार्थियों को सम्पूर्ण व्यक्ति बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था को अपनाना होगा। उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार, देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना

होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है लेकिन अकेले सरकार के दम पर यह बदलाव लाना संभव नहीं है। इसमें निजी विश्वविद्यालयों को भी भागीदारी निभानी होगी। यूनिवर्सिटी के संस्थापक, पद्मभूषण डॉ. एस.बी. मजूमदार ने गोल्ड मेडल प्राप्त विद्यार्थियों से कहा कि आपको

शिक्षा जरूर पूरी हो गई हो लेकिन सीखने की शुरुआत अब होगी। आपको आगे चलकर समाज का सामना करना होगा। अच्छे और बुरे अनुभव भी होंगे। उन्होंने कहा कि वो अनुभव किसी भी प्रोफेसर की तुलना में आपको ज्यादा शिक्षा देंगे। डॉ. मजूमदार ने छात्र-छात्राओं से कहा कि कभी उम्मीद न छोड़ें। वाइस चांसलर

डॉ. संजय कुमार ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में 70 फीसदी व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। तीस से ज्यादा प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है। यूनिवर्सिटी में 20 विद्यार्थियों के समूह पर एक शिक्षक उपलब्ध कराया गया है।

नागरिकता विधेयक : गृह मंत्री शाह ने तीन उत्तर पूर्वी राज्यों के नेताओं से की बातचीत

नई दिल्ली ए। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर शनिवार को असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों, छात्र एवं नागरिक संगठनों के साथ बातचीत की। कांग्रेस पार्टी की असम और त्रिपुरा इकाई जबकि त्रिपुरा की सीपीआई(एम) इकाई ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। शाह 3 दिसंबर को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएसयू) के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा, जिन संगठनों के साथ उनकी चर्चा का कार्यक्रम है उनमें नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एवं मेघालय, नगालैंड और शेष पृष्ठ 7 पर

निजी दूर संचार कंपनियों को लाभ दे रही है सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सरकार पर निजी क्षेत्र की दूर संचार कंपनियों के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (एमटीएमएल) को कमजोर कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी शेष पृष्ठ 7 पर

मोदी और शाह हैं घुसपैठिए: चौधरी

नई दिल्ली ए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की घुसपैठिया बता दिया है। एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'हिंदुस्तान सबके लिए है। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका समान अधिकार है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आप खुद घुसपैठिये हैं। घर आपका गुजरात है, आ गए दिल्ली। आप खुद माइग्रेट हैं। वैध-अवैध बाद में पता चलेगा।'

हैदराबाद रेप-मर्डर केस : आरोपी की मां ने कहा- 'जैसे उन्होंने किया, वैसे ही जिंदा जला दो'

हैदराबाद ए. हैदराबाद में डॉक्टर के निर्मम रेप और हत्याकांड के आरोपियों के परिवारों ने साफ कहा है कि उनके बेटों को अगर मौत की सजा दी जाती है तो वे विरोध नहीं करेंगे।

एक आरोपी की मां ने यह भी कहा है कि जैसा पीड़िता के साथ किया गया, वैसे ही आरोपियों को जला देना चाहिए। बता दें कि हैदराबाद के इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सड़क

करीबी बताते थे मावी सीएस

विभागीय सूत्रों ने बताया कि गौरी सिंह के करीबी विभाग में उन्हें मग्न का भावी मुख्य सचिव बताते थे। बताया गया कि कुछ बैठकों में उन्होंने खुद को भविष्य का मुख्य सचिव भी बताया था। इसी वजह से विभाग में उनकी तुली भी बोलती थी।

'मेरी भी एक बेटी, परिवार का दर्द समझती हूं'

मामले में घात में से एक आरोपी सी केएसुलु नाटाराणपेट जिले के मकदम मंडल के सुडीगाडला गांव का निवासी है। उसकी मां रथामला ने कहा है, 'उसे फांसी दे दीजिए या जला दीजिए, जैसे उन लोगों ने डॉक्टर के साथ किया उसका रेप करने के बाद। वह डॉक्टर के परिवार का दर्द समझती है। उन्होंने कहा, 'मेरी भी एक बेटी है और मुझे पता है कि महिला का परिवार दर्द से गुजर रहा है। अगर ये पता लेने के बावजूद कि मेरे बेटे ने गंजवट अपराध किया है, मैं उसका बचाव करूँ तो लोग मुझसे सारी जिंदगी ताकट करेंगे।

से लेकर सोशल मीडिया तक पीड़िता डॉक्टर के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। शेष पृष्ठ 7 पर

राष्ट्रपित से रॉ में रहे अफसर ने मांगी इच्छा मृत्यु

सचिव स्तर के अधिकारी (से.नि.) एससी कुमार ने राष्ट्रपति कोविंद व पीएम मोदी को लिखा पत्र

नवप्रदेश संवाददाता

नई दिल्ली। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में सालों तक सेवा दे चुके सचिव स्तर के से.नि अधिकारी एससी कुमार ने इच्छामृत्यु की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

को पत्र लिखा है। 80 साल के कुमार ने अपने इस कदम के पीछे एक रसूखदार नेता व हरियाणा शासन-प्रशासन के लचर रुख को जिम्मेदार बताया है।

पूर्व अफसर की आपबीती उन्हीं की जुबानी

कुमार ने कहा कि वे अभी गुरुग्राम स्थित पालम विहार के पार्क-व्यू रेसिडेंट्स बेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वहां के आठ टावरों में कुल 680 फ्लैट्स हैं। पार्क-व्यू गुरुग्राम सबसे बेहतरीन शेष पृष्ठ 7 पर

सुरक्षा

सीमा पर ड्रॉन्स से निपटने तकनीक पर काम कर रही है बीएसएफ : डीजी

सीमा पर नापाक ड्रोन, भारत की बड़ी तैयारी

एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिशें सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रही ही हैं, पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रॉन का खतरा बढ़ा है जो पाक की नापाक साजिश का हिस्सा है।

नई दिल्ली ए। बॉर्डर सिक्वॉरिटी फोर्स पाकिस्तान की इस साजिश से निपटने के लिए तकनीकी हल पर काम कर रही है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल वी. के. जोहरी ने कहा कि इस नए खतरे से निबटने के लिए हम कुछ अहम कदम उठा रहे हैं। बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर बीएसएफकैप में रेंजिंग डे इवेंट को संबोधित करते हुए जोहरी ने कहा कि फोर्स ने अपनी 'रणनीतिक क्षमता' को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी 6,386 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए फोर्स ने नई तकनीक और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी 'रणनीतिक क्षमता' का विस्तार किया है।



हर कोशिश नाकाम करने बीएसएफ सतर्क डीजी जोहरी ने कहा कि भारत-विरोधी ताकतें

ड्रॉन्स के खतरे से निपटने के लिए उठा रहे अहम कदम : डीजी

बीएसएफके डीजी ने कहा कि हाल के समय में कश्मीर में नियंत्रण रेखा और पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत 'संवेदनशील' बन गए हैं। जोहरी ने कहा, 'हाल के समय में हमें पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान के साथ) पर ड्रॉन्स की गतिविधियों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं और हम इसके टेक्निकल सलूशन (तकनीकी समाधान) पर काम कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।'

लगातार सीमापार घुसपैठ की कोशिशें कर रही हैं और बीएसएफ इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए हर वक्त सतर्क है। शेष पृष्ठ 7 पर

हफ्ते के बाद 28 नवंबर को कांग्रेस विधायकों को यहां से कोलाबा के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया गया।

जिला योजना समिति को अधिकार संपन्न बनाएगी मध्यप्रदेश सरकार

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। कमलनाथ सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जिला योजना समितियों को अधिकार संपन्न बनाएगी। इसके लिए 17 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया जा सकता है। वरिष्ठ सचिव समिति योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्तावित विधेयक पर मंथन कर चुकी है। इसमें जिला योजना समितियों को दो करोड़ रुपए तक के कामों को मंजूरी देने के अधिकार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तबादले भी समिति की सिफारिश पर प्रभारी मंत्री की अनुमोदन से होंगे। विकासखंडों को दो करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में



16 साल पहले लागू जिला सरकार के मॉडल को संशोधित स्वरूप में लागू करने की तैयार कर रहे हैं। इसमें जिला योजना समिति का दायरा बढ़ाया जाएगा। समिति के सदस्यों की संख्या में दो से तीन सदस्य और बढ़ाए जाएंगे ताकि जिला स्तर पर राजनीतिक जमावट बेहतर की जा सके। समिति को प्रदेश में भाजपा सरकार आने

के बाद कोई खास अधिकार नहीं रह गए थे। इसकी बैठकें भी औपचारिकता बनकर रह गई थीं। उधर, जिला पंचायतों की समितियां भी कमजोर कर दी गईं। त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन ने इसको लेकर शिवराज सरकार में कई आंदोलन भी किए पर विकास निधि देने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार अपने के

बाद जिला सरकार मॉडल पर फिर से विचार-विमर्श शुरू हुआ। इसके तहत जिला योजना समितियों को अधिकार संपन्न बनाने का मसौदा तैयार किया गया। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिला योजना समिति में बदलाव का मसौदा बनाकर मुख्य सचिव कार्यालय को कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा चुका है। वरिष्ठ सचिव समिति 23 सितंबर को बैठक करके इसके सभी पहलुओं पर विचार कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि मसौदे के मुताबिक समितियों को निरीक्षण, कार्रवाई करने के अधिकार देने के साथ जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद करने तबादले करने के अधिकार भी समितियों को दिए जाएंगे। समिति तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों की सिफारिश करेंगी। इस पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कार्रवाई होगी।

वहीं, समिति को दो करोड़ रुपए तक के निर्माण सहित अन्य कार्यों को स्वीकृति देने के अधिकार होंगे। राशि किसी एक क्षेत्र विशेष में खर्च न हो जाए, इसके लिए विकासखंडवार फंड दिया जाएगा। समिति की बैठकें हर तीन माह में होना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करेंगे। समिति जिले की सालाना विकास योजना को भी मंजूरी देगी। इसके आधार पर राज्य की वार्षिक योजना तैयार की जाएगी।

विस सत्र के बाद आकार लेगा योजना आयोग

सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद राज्य योजना एवं नीति आयोग आकार लेगा। इसमें मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष नामांकित करेंगे, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव होगा। यह नियुक्ति राजनीतिक होगी। इसके अलावा दो उपाध्यक्ष वित्त मंत्री और योजना,

साल 2019 में मध्य प्रदेश के हर दूसरे नागरिक ने रिश्तत देकर कराया काम

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। साल 2019 में मध्य प्रदेश के हर दूसरे आदमी ने रिश्तत देकर अपना काम कराया है। पिछले एक साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले दिनों आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और संस्था लोकल सर्किल द्वारा किए सर्वे की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। संस्था के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार स्थानीय निकायों में है। रिश्तत देने वाले मामलों में 38 फीसदी लोगों ने नगरीय निकाय में, 37 फीसदी लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में, जबकि 25 फीसदी लोगों ने परिवहन, बिजली कंपनी, टैक्स कार्यालय में



रिश्तत देकर काम कराया है। वहीं, 22 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार रिश्तत देकर ही काम कराया है। जबकि, 33 फीसदी लोगों का कहना था कि उन्होंने एक या दो बार रिश्तत देकर काम कराया है। सिर्फ 12 फीसदी लोगों ने कहा कि उनका काम बिना रिश्तत दिए हुआ है। सर्वे के दौरान 33 फीसदी

लोगों ने इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

ऐसे किया गया सर्वे

संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिश्तत का स्तर जानने के लिए देशव्यापी स्तर पर यह सर्वे किया। इसके लिए देशभर में करीब 40 हजार लोगों को सर्वे में शामिल किया

गया। इसमें से करीब 2200 लोग मध्यप्रदेश के थे। उन्हीं के जवाब के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

35 फीसदी लोगों ने रिश्तत में नकदी दी

सर्वे में 16 फीसदी लोगों ने बताया कि कंप्यूटराइज्ड कार्यालय में जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, वहां रिश्तत देना पड़ी। 28 फीसदी लोगों ने कहा कि जहां रिश्तत दी वो कंप्यूटराइज्ड कार्यालय तो था, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। 19 फीसदी लोगों ने कहा कि बिना कंप्यूटर और सीसीटीवी लगे कार्यालय में उन्होंने रिश्तत दी।

मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों से बिकेगा 80 फीसदी यूरिया खाद, अफसरों की टीम करेगी निगरानी

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रदेश में किसानों को यूरिया की बढ़ती मांग को देखते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से 80 फीसदी बिक्री की रणनीति बनाई है। अब सिर्फ 20 प्रतिशत यूरिया ही निजी विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कालाबाजारी न हो पाए और किसानों को उचित दर पर ही खाद मिले। सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को जिलों में सक्रिय रहने और बिजली व खाद जैसे मामलों को लेकर किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने कलेक्टरों को अधिकारियों की टीम बनाकर व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए कहा है। प्रदेश में खेी फसलों के अनुकूल मौसम को देखते हुए यूरिया की मांग बढ़ गई है। केंद्र से

तय कोटे से कम यूरिया मिलने के बावजूद अभी तक किसानों को 77 हजार मीट्रिक टन यूरिया अधिक दिया जा चुका है। किसानों को यूरिया मिलने में परेशानी न हो इसलिए सहकारी समितियों के माध्यम से 80 प्रतिशत बिक्री होगी। सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को नकद और साख (क्रेडिट), दोनों तरह से यूरिया दिया जाएगा। ऐसे किसान, जिनकी कर्ममाफी अभी प्रक्रिया में है, उन्हें भी समितियों से खाद मिलेगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने बताया कि अगले दस दिन में दो लाख मीट्रिक टन यूरिया आ जाएगा। 60 रैक यूरिया परिवहन में है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जिले में यूरिया का स्टॉक समान रूप से वितरित कराएं ताकि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सके।

विवाह समेलन



भोपाल (नवप्रदेश) । जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कलार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवदम्पतियों को आशीर्वाद दिया ।

श्रद्धांजलि

विश्वकर्मा विराट संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. कांतिभाई पांचाल को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय कांतिभाई पांचाल की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा में आयोजित किया गया। जागिड़ ब्राह्मण जिला सभा भोपाल के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने मंच का कुशल संचालन किया। सभा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यकारी राष्ट्रीय



अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी वीके विश्वकर्मा पांचालरत्न भोपाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये कहा कि स्वर्गीय कांतिभाई पांचाल जीवनपर्यंत असहाय एवं कमजोर वर्गों के हित का कार्य करते रहे।

उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ की ओर से गहरी शोक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत

आत्मा को श्री प्रभु चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार दुःख सहने को शक्ति प्रदान करें। जिला सभा भोपाल के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे विराट व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी अभिनव सोच, अपने कुशल नेतृत्व एवं रचनात्मक पहल से अपने शहर ही नहीं, अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में नाम रोशन किया है। उनके चारणों में कोटि-कोटि नमन। कोषाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि कर्मयोगी स्व. कांतिभाई पांचाल समाज उत्थान एवं विकास के लिये सदैव लड़नेवाले जीवट योद्धा और जननायक को खोने का दुःखद

अहसास हमें अंदर तक झकझोर दिया। समाज ने आज एक दुर्लभ रत्न खो दिया है। समाज को दी गई आपकी सेवाओं के लिए आपको शत शत नमन। सचिव कृष्ण रंजन शर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा पांचाल समाज के विकाश में अहम भूमिका निभाने वाले और वरिष्ठ समाजसेवी श्री कांतिभाई पांचाल का आकस्मिक निधन से समाज के बीच कि मानो किरण गायब हो गई है। शोक संदेश में प्रदेश संगठन मंत्री गेंदमल पांचाल ने कहा कि स्व. कांतिभाई पांचाल बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहे जिसके फलस्वरूप उनपर किसी प्रकार का आरोप जीवनपर्यन्त नहीं लगा।

उनके बताए हुए मार्गों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री नेता रमेश विश्वकर्मा पत्रकार इंदौर ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का हाथ पीला करने में कभी पीछे नहीं रहे। इसलिए दिवंगत कांतिभाई पांचाल का कमजोर वर्गों के हित में कार्य सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चन्द्र पांचाल उज्जैन ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि समाज ने एक बहुआयामी व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संत खो दिया है जिसके फलस्वरूप केवल गुजरात राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के सकल समाज मे शोक की लहर व्याप्त है।

रज भोपाल रज में तीन हजार प्रतिभागियों के साथ दौड़े मंत्री-विधायक, स्वच्छता का संदेश दिया

भोपाल। शहर में रविवार को रन भोपाल रन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर शहर को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रतिभागियों को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी दौड़ लगाई। इस मौके पर विधायक अरिफ मसूद और कांग्रेस नेता गोविंद गोयल भी मौजूद थे। दौड़ में करीब तीन हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।



तीन तरह की दौड़ 21 किमी दौड़ : मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ पीएचक्यू, खटलापुरा, केपन प्रधान तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, रेतघाट होकर करबला पंप हाउस से यू-टर्न लिया। यहां से रेतघाट, भारत भवन, बोट क्लब से होकर मानव संग्रहालय में प्रवेश करते हुए मानव संग्रहालय गेट-2 से डिपो चौराहा, भदभदा चौराहा, सैर सपाटा के सामने से यू-टर्न लेकर भदभदा चौराहा, रंगमहल चौराहा से टीटी नगर के गेट-2 से स्टेडियम पहुंची।

11 किमी की दौड़: मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर पीएचक्यू, खटलापुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा, करबला पंप हाउस से यू-टर्न लेकर वापस पॉलिटेक्निक, पलाश होटल तिराहा से टीटी नगर स्टेडियम पहुंची।

5 किमी : मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से पॉलिटेक्निक चौराहा से बाणगंगा चौराहा, पलाश होटल तिराहा होते हुए स्टेडियम पहुंची।

न्यूज गैलरी

प्रदेश में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नाकाफी, अधिकारियों पर कार्रवाई की दरकार

भोपाल।मद्र में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृति देकर शासन-प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, कारण ये परीक्षा उर्तीर्ण न कर पाये। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैलाल लक्षकार ने कहा कि 16 शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृति न्यायोचित नहीं है। पंचा शिक्षा नीति, बगैर रोक के कक्षोन्नति, भयमुक्त शिक्षा को लागू करते भयभीत शिक्षक, विद्यालयीन समय में प्रशिक्षण के नाम पर बच्चों को पढ़ाने न देना, बिगड़ा शिक्षक छात्र अनुप्रात, शिक्षकों की कमी व नई नियुक्तियों को वर्षों से टालना, माननीय न्यायालय एवं विभागीय आदेशों के बाद भी गैर शैक्षणिक कार्य बदस्तूर जारी रखना, छात्रवृत्ति, सायकिल वितरण, ग्राम/नगर शिक्षा रजिस्टर सर्वे, एमडीएम, वॉशिल पाठ्यक्रम ऐसे अनेकानेक कारण राज्य शिक्षा केंद्र की स्थापना के साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था को चोट करने का मुख्य कारण है । प्रहार यहाँ होना था, आम शिक्षक चिंतन करता कि पूर्व में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को नीति नियंताओं ने चोपट किया है, इसमें शिक्षक कहाँ दोषी हैं ? इन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं । इनकी नियुक्ति से लेकर सेवानिवृति दिनांक तक के सेवाकाल का परीक्षण किया जावे । यदि शिक्षक अयोग्य हैं तो इनके नियोका से लेकर अभी तक वे विभागीय अधिकारी सबसे पहले दोषी हैं, जिनके अधिन ये कार्यरत रहे, प्रशिक्षक व प्रशिक्षण व्यवस्था में कार्यरत संपूर्ण अमला, उनके साथ समस्त विभागीय/गैर विभागीय निरीक्षणकर्ताओं व गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न करने वाले राजस्व अधिकारियों तहसीलदार /एसडीएम /क्लेक्टर को जो सबसे पहले सेवा में है तो सेवानिवृति देकर व सेवानिवृत्त ही चुके तो उनकी चल -अचल संपत्ति से प्रभावित शिक्षकों के वेतन भत्तों की भरपाई भी इनसे करना न्यायोचित होगा । शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृति से संफेद हाथी व बड़ी मछलियां अपने आप को बचाने का कुत्तिस प्रयास कर कामयाब रहे ; जिसे किसी भी हालत में अन्देखा नहीं किया जाना चाहिए । मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान कमलनाथ जी व शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमान प्रभुराम चौधरी व जनसंपर्क मंत्री माननीय श्रीमान पीसी शर्मा जी मप्र शासन भोपाल से मांग करता है कि प्रभावित शिक्षकों के मामले में संवेदनशील होकर बहाल कर शिक्षा विभाग के अंदर पढ़ाने के अलावा अनावश्यक डाक व गैर जरूरी प्रशिक्षण से मुक्त रखकर संपूर्ण सत्र केवल पढ़ाई -लिखाई का कार्य करने दें ; निश्चित तौर से शिक्षा के स्तर में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा । शिक्षकों को षडयंत्र के तहत पढ़ाने नहीं देते व बेहतर परिणाम की आशा बेमानी होगी । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मेदानी अमले के सुझाव लेकर सख्ती से पालन हो, वॉछित परिणाम मिलना तय है । सरकार पर रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का उपाा लगने से लाखों कर्मचारियों की भावनाएं आहत तो हुई है साथ ही गहरी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है । इतिहास गवाह है कर्मचारियों की बेरुखी कभी भी सत्ताधारी दल के लिए राजनीतिक रूप से शुभ नहीं रही है । प्रकरण पर पुर्नविचार किया जाकर प्रभावित शिक्षकों को बहाल करना ही चाहिए ।

स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़े पूर्वोत्तर के राज्य, मध्य प्रदेश सबसे आगे

भोपाल।देश के सी शहरों को अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस करने के लिए शुरू की गई सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य फिसड़ी साबित हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश इस मामले में अन्य राज्यों से काफी आगे है. शहरी जीवन को आसान बनाने (ईज ऑफ़ लिविंग) के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जुन 2015 में शुरू की गई इस परियोजना की प्रगति की राज्यवार समीक्षा की गई है. इस समीक्षा के तहत पिछले पांच सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्र की ओर से जारी की गई राशि में से कई राज्य अभी आधी राशि का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं. मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में सभी राज्यों के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक 186।14.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. राज्य इसमें से ९497.09 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) का इस्तेमाल कर पाए हैं. इसके अनुसार स्मार्ट सिटी के तहत इन शहरों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की पूर्वोत्तर राज्यों में न सिर्फ गति बहुत धीमी है बल्कि तमाम शहर इस राशि का पैसा भी खर्च करने में सुस्त हैं. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और रामपुर, पश्चिम बंगाल के बिधाननगर, दुर्गापुर और हल्द्वीच, महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई और अमरावती तथा तमिलनाडु के डिंडीगुल को पांच साल में महज दो करोड़ रुपये ही केन्द्रीय राशि मिली है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने इन शहरों से परियोजनाओं के प्रस्ताव नहीं मिलने को कम राशि जारी होने की मुख्य वजह बताया है.

2.05 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले

परियोजना की प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 नवंबर तक परियोजना में चयनित 100 शहरों की ओर से 2.05 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले कुल 5।151 परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को मिले. इनमें से 1.49 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 4178 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गईं. 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3376 परियोजनाओं का काम जारी है और 23170 करोड़ रुपये की लागत से 1296 परियोजनाओं पूरी कर दी गई हैं.

अरुणाचल प्रदेश की परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है

परियोजना की राज्यवार समीक्षा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के दो शहरों में एक भी परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि असम के गुवाहटी में अब तक सिर्फ पांच परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया, इनमें से दो ही पूरी हो पाई. मणिपुर और मेघालय का रिपोर्ट कार्ड भी शून्य है और सिक्किम में सिर्फ एक परियोजना पूरी हुई. इस मामले में सिर्फ त्रिपुरा, नगालैंड और मिजोरम में लाभग आधी परियोजनाएं पूरी हो सकी हैं. जम्मू कश्मीर के दोनों शहरों जम्मू और श्रीनगर को 20 स्वीकृत परियोजनाओं में से एक भी पूरी नहीं हो सकी और पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन कोलकाता में 56 में से महज 1.1 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनायें पूरी हो सकी. स्मार्ट सिटी की दौड़ में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे आगे हैं.

न्यूज गैलरी

सैयद मोदी बैडमिंटन में उपविजेता रहे

सौरभ वर्मा

लखनऊ । गैर वरीय भारत के सौरभ वर्मा को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में रविवार को हारने के बाद उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 36वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी सौरभ को फइनल में आठवीं सीड ताइपे के वांग जू वेई से 48 मिनट में 15-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। सौरभ का 22वीं रैंकिंग के जू वेई के खिलाफ इससे पहले 1-1 का करियर रिकॉर्ड था। भारतीय खिलाड़ी ने दोनों गेमों में सराहनीय संघर्ष किया लेकिन उन्हें उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा।

पुनीत और ओमपाल युग स्पोर्ट्स क्वार्टर फाइनल में

नयी दिल्ली । पुनीत महारा के हरफनमौला खेल (77 और 35 पर तीन विकेट) और ओमपाल बोकन के विस्फोटक 80 रन तथा पवन के चार विकेट और तरुण गोदारा के नौ गेंदों पर 38 रनों की बढ़तील मेजबान युग स्पोर्ट्स ने अमिगोस स्पोर्ट्स अकादमी को रोमांचक मैच में 22 रन से हराकर प्रथम आर एन सिंह टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत हासिल कर क्वाटर फ़ाइनल में प्रवेश कर लिया। युग स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स कादरपुर पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में युग स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 230 रनों का विशाल स्कोर बनाया जिसमे ओमपाल ने 80, और पुनीत महारा ने 77 बनाये।

ओडिशा-पंजाब मुकाबले में मैरीकॉम रहेगी मुख्य आकर्षण

नई दिल्ली । ओडिशा वॉरियर्स और पंजाब पैथर्स के बीच सोमवार को होने वाले मुकाबले के साथ ही बिग बाउट लीग का शुभारम्भ हो जाएगा। गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा में होने वाले मुकाबले का मुख्य आकर्षण छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम रहेगी जो पंजाब पैथर्स की ओर से फ्लाईक्रेट वर्ग में चुनौती रखेंगी। मैरीकॉम ने कहा कि इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कुछ हुआ,

एजीएम खत्म, 2024 तक बढ़ सकता है गांगुली का कार्यकाल

बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली के 9 महीने के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति मिल जाती है तो 2024 तक चलेगा गांगुली का टर्म

2003 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम इंडिया के कप्तान रहे गांगुली ने 23 अक्टूबर को संभाला था पद

मुंबई (ए.)। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के नेतृत्व वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल की सीमा में ढिलाई देने को स्वीकृति दे दी। बीसीसीआई की यहां आयोजित 88वीं वार्षिक आम बैठक



(एजीएम) में यह फैसला लिया गया। इससे बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली के 9 महीने के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड की एजीएम

2024 तक बढ़ेगा कार्यकाल?

बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के लिए शीर्ष अदालत में भेज दिया जाएगा।’ यदि स्वीकृति मिल जाती है तो गांगुली साल 2024 तक बीसीसीआई चीफबने रह सकते हैं।

वर्ल्ड कप की फ़ाइनलिस्ट टीम इंडिया के कप्तान रहे गांगुली के बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एजीएम आयोजित की गई।

ऐसा है मौजूदा नियम

मौजूदा संविधान के अनुसार अगर किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई या राज्य संघ में मिलाकर तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं जो उसे तीन साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा। गांगुली ने 23 अक्टूबर को बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला था और उन्हें अगले साल पद छोड़ना होगा लेकिन छूट दिए जाने के बाद वह 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं।

बदली थी टीम इंडिया की तस्वीर

क्रिकेट फैंस के बीच ‘दादा’ कहे जाने वाले सौरभ की इमेज घातक बल्लेबाज की रही। जब वह बल्लेबाजी करते थे तो दो कदम आगे निकलकर दर्शनीय सितसर देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। ऑफसाइड के भगवान कहे जाने वाले गांगुली को 2000 में उस वक्त लीडरशिप का मौका मिला, जब भारतीय क्रिकेट को मैच फिक्सिंग से दो-चार होना पड़ा था। गांगुली ने कप्तानी संभाली और फिर दुनिया को एक महान लीडरशिप से रूबरू करवाया। वर्ल्ड कप-2003 में गांगुली की ही कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया, जिसने भारतीय क्रिकेट को बदलकर रख दिया।

टेस्ट मैच के लिए सहवाग ने प्रेरित किया : वॉर्नर

जब IPL में सहवाग से मिले थे वॉर्नर तब उन्होंने टेस्ट के प्रति किया था प्रेरित

शुरुआत में टेस्ट करियर को लेकर संशय में थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वॉर्नर

‘सहवाग की सलाह के बाद हमेशा दिमाग में वही रहा, जो उन्होंने समझाया’

एंडिलेड (ए.)। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में सर डॉन ब्रैडमैन के सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर को पीछे छोड़ने वाले डेविड वॉर्नर ने अपनी इस पारी की प्रेरणा वॉरेंडर सहवाग को बताया है। वॉर्नर ने अपनी इस पारी के बाद खुलासा किया कि आईपीएल में जब वह वॉरेंडर सहवाग से मिले तो टेस्ट क्रिकेट के प्रति सहवाग ने ही उनका माइंडसेट चेंज किया था। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने बताया कि वह कभी अपने टेस्ट करियर को लेकर संशय में थे लेकिन सहवाग की सलाह के बाद वॉर्नर ने उस पर अमल किया।

इस टेस्ट में नाबाद 335 रन की पारी खेलने वाले वॉर्नर ने संवाददाताओं को बताया, 'आईपीएल के दौरान दिल्ली के लिए खेलते हुए जब मैं वॉरेंडर सहवाग से मिला था। तब हम एक दिन बैठकर आराम से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मैं टी20 खिलाड़ी की तुलना में बेहतर टेस्ट खिलाड़ी बनूंगा। मैंने उन्हें (सहवाग को) कहा कि आप कैसी बातें



लारा का रिकॉर्ड टूटेगा?

वॉर्नर को रोहित पर भरोसा

वॉर्नर ने कहा, ‘सहवाग की इस सलाह के बाद यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रही। जब हम बातें कर रहे थे तो ये चीजें काफी आसान लग रही थीं।’ इसके अलावा वॉर्नर ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा दौर का कोई बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा का (400 रन का) सर्वाधिक रन वाला रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वह भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 335 रन बनाने वाले वॉर्नर का यह पहला तिहरा शतक है।

कर रहे हो? मैंने काफी प्रथम श्रेणी मैच भी नहीं खेले हैं।' इसके बाद पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज सहवाग ने वॉर्नर की बैटिंग शैली का विश्लेषण कर वॉर्नर को समझाया कि आखिर वह क्यों ऐसा सोच रहे हैं। सहवाग ने वॉर्नर से कहा था, 'टेस्ट क्रिकेट में टीमें स्लिप और गली में फील्डर खड़ा करती हैं। कवर में जगह खाली होती है, मिडविकेट होता है। मिड ऑफ और मिड ऑन होते हैं। ऐसे में आप तेज शुरुआत कर सकते हो और पूरा दिन खेल सकते हो।'

पृथ्वी के बल्ले पर किसका ऑटोग्राफ? बर्न्स और जो रूट ने ठोके शतक

कप्तान विराट कोहली और विनोद कांबली के बीच लोग हुए कन्फ्यूज

बीसीसीआई डॉमेस्टिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पृथ्वी के बल्ले का फोटो टवीट किया गया है

नई दिल्ली (ए.)। मुंबई के युवा बल्लेबाज पृथ्वी साव प्रतिभाशाली कहे जाते हैं। उनके बैट पर किसी दिग्गज बल्लेबाज के हस्ताक्षर हैं और यही सवाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूछा है। बीसीसीआई डॉमेस्टिक के



आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पृथ्वी के बल्ले का फोटो टवीट किया गया है। बीसीसीआई ने पूछा, पृथ्वी साव के बल्ले पर

किसका ऑटोग्राफ है? इस युवा बल्लेबाज के बैट पर एक छोटा मैसेज लिखा है, डियर पृथ्वी, खेल का मजा लो, गुड लक। इसी संदेश के नीचे की तरफ ही ऑटोग्राफ है।

इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब दिए। किसी ने इसे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बताया तो वहीं, कुछ लोगों को यह ऑटोग्राफविनोद कांबली का लगा। कुछ लोगों ने यह लिखा कि ऑटोग्राफ विराट के हैं, लेकिन विनोद कांबली से काफी मिलते

जुलते हैं। मीना नाम के एक यूजर ने विराट कोहली के ऑटोग्राफका फोटो भी इसके जवाब में पोस्ट किया। पृथ्वी ने डोपिंग के कारण आठ महीने का बैन झेला और इसके बाद शानदार अंदाज में वापसी की। पृथ्वी साव ने वापसी के बाद अपने पहले मैच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 में पंजाब के खिलाफ 27 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली और शानदार अर्धशतक जमाया।

हैमिल्टन । ओपनर रोरी बर्न्स (101) और कप्तान जो रूट (नाबाद 114) के शानदार शतकों से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को पांच विकेट पर 269 रन बना लिए।

इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड पहली पारी के 375 रन के स्कोर से 106 रन पीछे है। इंग्लैंड ने दो विकेट पर 39 रन से आगे खेलना शुरू किया। बर्न्स ने 24 और रूट ने 6 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की



साझेदारी की। बर्न्स ने 209 गेंदों पर 101 रन में 15 चौके लगाए

हैं। बर्न्स का विकेट 201 के स्कोर पर गिरा। बर्न्स अपना शतक पूरा करने के बाद रन आउट हुए।

रूट ने फिर बेन स्टोक्स के साथ छठे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। स्टोक्स ने 59 गेंदों पर 26 रन में चार चौके लगाए। जैक क्राउली एक रन बनाकर आउट हुए। अंतिम सत्र में बारिश आने के कारण 16 ओवर का खेल बर्बाद हुआ। स्टैप्स के समय रूट के साथ ओली पोप चार रन बनाकर क्रीज पर थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष

प्रदेश सरकार के निशाने पर

ध्यान में रखते हुए अधिकारी की सक्रियता और दक्षता को महत्व देती नजर आ रही है। यह संकेत ग्रामीण विकास विभाग में वर्तमान में की गई पदस्थापना से भी नजर आ रहे हैं और इस परिवर्तन से सरकार ने आईएएस एसोसिएशन को भी एक आइना दिखा दिया है।

अब देखना यह है कि पिछली सरकार के अपर मुख्य सचिव के विवादित निर्णयों से बदहाल हुए विभाग की बदहाली पर उनके बाद के अपर मुख्य सचिव जहां कुछ खास न कर सके वहीं वर्तमान सरकार के अपर मुख्य सचिव भी उस बदहाली पर ध्यान न देते हुए अन्य विषयों में विवादित रहे। ऐसी स्थिति में बदहाली से बेपटरी हुए विभाग को पुनः पटरी पर लाने की कवायद में यह परिवर्तन कितना सार्थक होगा यह तो समय और अधिकारी की स फ ि क ष य त ा

ही बताएगी।

मुख्यमंत्री की नाराजगी पर गौरी

निजी कॉलेजियों के लिए वाल्मी से रास्ता देने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे। यह मामला भी मुख्यमंत्री तक पहुंचा था।

राष्ट्रपति से रा में...

आवासीय समूह का खिताब कई बार जीत चुका है। लेकिन पिछले दो साल से एक राजनेता जवाहर यादव के प्रभाव में आकर आरडब्ल्यूए को परेशान किया जाने लगा। कारण- सिर्फ आरडब्ल्यूए पर अपने लोगों को बिठाकर मनमंजी चलाने का है। उक्त राजनेता का प्रभाव हरियाणा सरकार पर इतना है कि न पुलिस सुनवाई करती है, और न ही शासन-प्रशासन। और तो और राज्य शासन से गफलत में डालकर, गलत जानकारीयां देकर येनकेन

प्राकरेण मौजूदा आरडबल्यूए को भंग करने की पुरजोर कोशिश जा रही है। कुमार ने आगे कहा कि चारों तरफ से फरियाद मांगने के बाद जब लगने लगा कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इस भागादौड़ का कोई अंजाम नहीं निकल रहा तो अंत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु का निवेदन किया है ताकि वर्षों रॉ जैसे संस्थानों में राष्ट्रभक्ति से काम करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर बिना वजह मुझे हर रोज शर्मसार न होना पड़े!

नागरिकता विधेयक...

अरुणाचल प्रदेश के छात्र संगठन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय और राज्य प्रमुख, दोनों सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुखों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के

खिलाफ पूर्वोत्तर में कई संगठनों की ओर से किए गए जोरदार प्रदर्शनों के मद्देनजर शाह यह बैठकें कर रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के मुख्यमंत्रियों क्रमशः सर्बानंद सोनोवाल, पेमा खांडू और कोनाई संगमा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू एवं कुछ सांसदों के साथ शनिवार की चर्चा में भाग लिया। खांडू ने रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय आदिवासी समुदायों की चिंताओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2016 के बिल्कुल खिलाफ है जो अब सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2019 के नाम से जाना जा रहा है।

निजी दूर संचार...

मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ निजी क्षेत्र को फायदा

पहुंचाना रह गया है और इसके लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को जानबूझकर कमजोर करने का उपक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल पूरे देश में उपभोक्ताओं की सेवा कर रही है। एमटीएमएल महानगरों में दूर संचार देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एक मात्र प्रमुख कंपनी रही है लेकिन आज यह दोनों कर्पनाय घाटे में चल रही हैं। इस सरकार ने इन दोनों कंपनियों को जानबूझकर कमजोर किया है। संग्रम के समय ये दोनों कंपनियां आठ हजार करोड़ रुपये के मुनाफे में थीं लेकिन आज 11228 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही हैं।

जैसे उन्होंने किया...

श्यामला ने बताया कि गुरुवार सुबह जब पुलिस उनके बेटे को पूछताछ के लिए लेकर गई तो उनके पति ने हताश होकर घर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि केशवतुल की शादी

पांच महीने पहले हुई थी। उन्होंने बताया, ‘हमने उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी कराई। घर पर कभी कोई दबाव नहीं डाला क्योंकि उसे किडनी की बीमारी थी। हम उसे हर 6 महीने पर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स अस्पताल ले जाते थे।’

हर कोशिश नाकाम करने बीएसएफ

बता दें कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्य काम भारत-पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी बीएसएफ अहम भूमिका निभाती है। बीएसएफ में करीब ढाई लाख अफसर और जवान हैं। दरअसल, हाल के समय में पंजाब में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए हथियारों और ड्रग्स को गिराने की कई घटनाएं सामने आई हैं।

न्यूज गैलरी

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 15 माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने कराया मुंडन



भोपाल। 15 महीनों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे 2719 उम्मीदवारों का सब्र का बांध टूट सा गया है। 24 नवंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू से पद यात्रा (संविधान रक्षा यात्रा) शुरू हुई और शनिवार को भोपाल पहुंची। शनिवार को यात्रा में शामिल लोगों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। रविवार को यात्रा शामिल लोग शहर में प्रवेश कर गए और नीलम पार्क में जम गए। शनिवार को जहां 27 लोगों ने मुंडन कराया था, वहीं आज भी ये लोग मुंडन करा रहे हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9037 में से 4727 पद खाली हैं। इनमें से करीब 3379 पदों पर भर्ती के लिए विभाग की डिमांड पर मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर लगभग 2719 उम्मीदवारों का चयन किया। यह उम्मीदवार पिछले 15 महीनों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे इन्हें पुलिस ने राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया। इन उम्मीदवारों को भैंसाखेड़ी के पास ही रोक दिया गया। इस यात्रा में लगभग 1500 उम्मीदवार शामिल हैं। कईयों के परिजन भी इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कई उम्मीदवारों के पैर में छले पड़ गए हैं। अब तक 100 से अधिक उम्मीदवार मुंडन करा चुके हैं। उम्मीदवारों का मुंडन करने वाले व्यक्ति भी पीएससी से फिजिक्स विषय में चयनित उम्मीदवार सागर सेन हैं। इन्होंने राज्य स्तरीय पाक्षता परीक्षा (सेट) क्वालिफाई किया है। इस पदयात्रा के दौरान इन्होंने भीख मांगकर पैर धरा। उम्मीदवारों का कहना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के हाल बेहाल हैं। इसके बाद भी लगातार आक्षासन मिलते रहे।

भोपाल में पहली बार, दो पेड़ काटने वाले पर एक लाख रु. का जुर्माना



भोपाल। बिना अनुमति पेड़ काटने वाले के खिलाफ नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने साकेत नगर 2-ए सेक्टर निवासी मो. सज्जाद पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सज्जाद ने एम्स के पास हाथ ही में नया मकान बनाया है। उनके घर के सामने आम के तीन पेड़ लगे थे। उन्होंने बिना नगर निगम की अनुमति के दो पेड़ काट दिए, जबकि तीसरे को काटने की तैयारी थी। इस दौरान सूचना पर एचओ रामरतन लोहिया मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उद्यान अधिकारी मनोज मौर्य को सूचना दी। बाद में यह मामला अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) राजेश राठौड़ और अपर आयुक्त (उद्यान) पवन सिंह तक पहुंचा। दोनों अपर आयुक्तों के निर्देश के बाद लोहिया ने कुल 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना किया। लोहिया ने कहा कि इस जुर्माने में आठ नए पेड़ लगाने, उनका संरक्षण करने और रास्ता जाम करने के कारण होने वाली परेशानी का जुर्माना व अन्य खर्च भी शामिल किए गए हैं। सज्जाद ने पेड़ काटकर एम्स जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था।

हनी ट्रैप मामले: कारोबारी के ठिकानों पर छापे, 3 एफआईआर दर्ज

कारोबारी और मीडिया संस्थान के मालिक के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

शनिवार देर रात कार्रवाई को दिया अंजाम, रविवार को दर्ज किया प्रकरण

हनी ट्रैप मामले के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप

नवप्रदेश संवाददाता

इंदौर। हनी ट्रैप मामले में नए खुलासे करने वाले मीडिया संस्थान के मालिक के ठिकानों पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। संस्थान के मालिक पर आईटी एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। संस्थान से जुड़े लोगों ने इसे बदले की भावना के तहत कार्रवाई बताया। शनिवार देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने कारोबारी और मीडिया संस्थान के मालिक जीतू सोनी के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। देर रात पुलिस कारोबारी के गीता भवन स्थित माय होम नामक होटल



पर पहुंची और जांच की कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई का कारोबारी द्वारा विरोध किया गया। पुलिस के साथ नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम भी थी। होटल में देर रात तक शराब परोसे जाने, लड़कियों द्वारा अश्लील नृत्य और अन्य अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पुलिस को मिली थी। रविवार सुबह कारोबारी द्वारा संचालित किए जाने वाले समाचार पत्र के कार्यालय को भी सील कर दिया गया। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले के

फरियादी इंदौर नगर निगम के अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर जीतू सोनी और अन्य के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

जेल में बंद महिला आरोपियों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी

इधर, वीडियो वायरल होने के बाद हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद महिला आरोपियों की ओर से जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने

हनीट्रैप मामले में आए दिन किए जा रहे थे नए खुलासे

बताया जाता है कि हनी ट्रैप मामले में पिछले कुछ दिनों से सोनी द्वारा संचालित समाचार पत्र में नए खुलासे किए गए थे। इनमें मप्र के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रमुख सचिव रहे एसके मिश्रा और इंदौर नगर निगम के अधिकारी हरभजन सिंह के हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद आरोपी महिलाओं के साथ संबंध उजागर किए गए थे। आरोपी महिलाओं के साथ बातचीत और कृत्य के वीडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

का निवेदन किया गया था। हालांकि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट को बताया था कि मामले से संबंधित जब्त किए गए वीडियो और वीडियो एसआईटी द्वारा किसी को नहीं दिए गए हैं और ना ही इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी जा रही है।

भाजपा महासचिव ने कहा- पत्रकार परिवार पर हुई कार्रवाई निंदनीय

हनी ट्रैप मामले में पुलिस द्वारा

अखबार मालिक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सच को उजागर करने वाले पत्रकार के परिवार पर हुई कार्रवाई निंदनीय है। विजयवर्गीय ने कहा है कि हम छापों के खिलाफ नहीं है ,लेकिन कोई पत्रकार सच को उजागर कर रहा है और उस पर बदले की नियत से कार्रवाई की जाए, छपे डाले जाए तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि

पात्रता परीक्षा में फेल 84 शिक्षक निशाने पर, 16 जबरन रिटायर

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में खराब प्रदर्शन और उसके बाद विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में फेल हुए 84 शिक्षक विभाग के निशाने पर है, इनमें से 16 शिक्षकों को आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में नाराजगी पैदा हो रही है। राज्य के कई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा स्तर का बुरा हाल होने से सरकार और विभाग दोनों चिंतित है। इसमें सुधार लाने के लिए विभाग शिक्षकों के ज्ञान का ही परीक्षण करने में लग गया है। इसी क्रम में उन शालाओं के शिक्षकों के पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जिनकी शालाओं के नतीजे 30 फीसदी से कम थे। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुमार चौधरी ने कहा, 'स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभाग द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के तहत पात्रता परीक्षा हुई और 84 शिक्षकों ने इन परीक्षाओं में 33 फीसदी से कम अंक पाए। इनमें से 16 शिक्षकों को आवश्यक सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए हैं।



शेष पर कार्रवाई जारी है।' गौरतलब है कि राज्य के उन स्कूलों के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जहां के नतीजे 30 फीसदी तक आए थे। ऐसे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जून में ली गई थी, जिसमें 5891 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1351 फेल हुए। इन शिक्षकों ने परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंक पाए थे। उसके बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा ली। बाद में पास होने के लिए 33 फीसदी अंक लाने की बाध्यता रखी गई। दूसरी बार में भी 84 शिक्षक 33 फीसदी से कम अंक ही हासिल किए और फेल हो गए। इन शिक्षकों ने पुस्तक के साथ

परीक्षा दी थी। शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी के अनुसार, इनमें से 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। अनुवीण हुए 26 शिक्षकों को चेतावनी देते हुए हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल से पदच्युत करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में भेजने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा, 'जिन शिक्षकों अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, उन्हें 20 साल की सेवा और 50 वर्ष की आयु के फॉर्म्युले के आधार पर दी गई है। 20 साल की नौकरी या 50 की उम्र के फॉर्म्युले से आने वाले 20 शिक्षकों की विभागीय जांच शुरू हो चुकी है।

मध्य प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन मामले में पूर्व विधायक सहित 7 को सजा

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हिंसक प्रदर्शन और थाना प्रभारी से मारपीट करने के मामले में सांसद-विधायकों के मामलों के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंदसौर में किसानों पर की गई गोलीबारी के विरोध में जून 2017 को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के करैरा में कांग्रेस की पूर्व विधायक



शकुंतला खटीक के नेतृत्व में भीड़ ने थाने पर पथराव किया था और तत्कालीन थाना प्रभारी से मारपीट भी की थी और इसके साथ ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया भी था। इस मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शकुंतला खटीक सहित सात

लोगों को तीन-तीन साल की कैद और 35 हजार का अर्थदंड दिया है। गौरतलब है कि मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड के विरोध में 8 जून, 2017 को कांग्रेस की तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करैरा में प्रदर्शन किया गया।

गड़बड़ी

पीडब्ल्यूडी विभाग ने ध्वस्त हुए पुलों से नजरें फेरीं, दोषियों पर कार्रवाई नहीं

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश में चंबल, कुनो और कुआरी जैसे पुलों के ध्वस्त होने पर खूब हंगामा मचा, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस मुद्दे से अपनी नजरें ही फेर लीं। निर्माण के चंग महीने बाद ही बड़े शिवपुरी जिले के कुनो पुल की जांच समिति ने तो गुणवत्ता अच्छी बता दी। सरकार अब कह रही है कि जांच रिपोर्ट का भी परीक्षण करवाएंगे। प्रदेश में शिवपुरी जिले में कुनो नदी पर बना पुल लोकार्पण के पांच महीने बाद



हीं बह गया। दुर्घटना के बाद मामले में खूब हंगामा हुआ, लेकिन जांच की

घोषणा कर मामला शांत कर दिया गया। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में पुल की गुणवत्ता अच्छी बता दी, जिसके आधार पर कोर्ट में संबंधित इंजीनियरों को राहत मिल गई। उधर, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना पुल भी भारी बारिश के चलते बह गया, पुल करीब नौ साल पहले बना था। इस दुर्घटना को कई महीने बीत गए, लेकिन जांच रिपोर्ट का वया हुआ कुछ पता ही नहीं चला। क्षेत्रीय नागरिकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई। इसके अलावा दोनों स्थानों पर नए पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को लेकर भी अभी कोई चर्चा

शुरू नहीं हुई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि भिंड जिले में ओमरी से पूफ गांव कुआरी नदी पर ध्वस्त हुए पुल पर पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। विभागीय विशेषज्ञों का कहना है कि पुल निर्माण के समय अधिकतम पानी और बाढ़ की स्थिति का पूर्व आकलन कर ही मजबूती का ध्यान रखा जाता है। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पाई। जांच समिति द्वारा पुल निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (गिट्टी, सीमेंट, रेत और सरिया) आदि का बिना प्रयोगशाला में परीक्षण कराए क्लीनचिट

दिया जाना समझ से परे है। मौके पर भौतिक निरीक्षण के बाद ही गुणवत्ता अच्छी बताकर निर्माण से जुड़ी एजेंसी और इंजीनियरों को क्लीनचिट दे दी गई है। विभागीय विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट नहीं किया कि इतना मजबूत पुल आखिर टूटा कैसे। समिति ने किसी को जिम्मेदार ही नहीं उठराया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट से संबंधित इंजीनियरों का निलंबन बहाल हो गया। चंबल नदी के मामले में अभी जांच ही शुरू नहीं हो पाई। कटनी-मैहर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के स्पाॅन में क्रैक आने की जांच अगस्त 2019 में हो गई,

भाजपा जिलाध्यक्षों के पैनल पहुंचे भोपाल, नाम चयनित करने के बाद होगा एलान

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा जिलाध्यक्षों के चयन के लिए संपन्न रायशुमारी के बाद संभावित नामों के पैनल रविवार को भोपाल पहुंच गए। पांच जिलों में अभी चुनाव प्रक्रिया अटक है, बाकी ज्यादातर जिलों में अब पैनल की स्क्रूटनी (नाम चयनित करने की प्रक्रिया) शुरू कर दी गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्षों की घोषणा में अभी एक-दो दिन का समय और लगेगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को दिनभर जिला चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला चलता रहा। जिलों में भेजे गए चुनाव अधिकारियों ने रायशुमारी के बाद जिन नामों का पैनल तैयार किया है, उन सभी के लिफाफे प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिए



हैं। अब इन सभी नामों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही जिलाध्यक्षों का एलान किया जाएगा। हर जिले से तीन-तीन नामों के पैनल बनाए गए हैं।

विवाद की स्थिति नहीं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को जिला चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ विचार-विमर्श के बाद

जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी जिले में विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

इन पांच जिलों में अटकी है प्रक्रिया

बताया जाता है कि सिवनी, होशंगाबाद, ग्वालियर, झाबुआ और शहडोल में रायशुमारी की प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है। इन पांचों जिलों में चुनाव की प्रक्रिया अभी अटकी है। झाबुआ में विधानसभा के उपचुनाव के कारण चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है, बाकी अन्य जिलों में कुछ दिन बाद रायशुमारी प्रारंभ की जाएगी। भाजपा संगठन के प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद केंद्रीय संगठन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

फिर शुरू होगा बरसात का दौर, ओले गिरने की भी आशंका

भोपाल। मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को रतलाम में एक मिमी. बरसात हुई। ऐसी स्थिति अरब सागर में एक साथ अलग-अलग स्थानों पर बने दो कम दबाव के क्षेत्र के कारण बनी है। मौसम विज्ञानियों ने दक्षिण-पश्चिम मप्र (इंदौर,उज्जैन,भोपाल,होशंगाबाद) में बरसात होने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। अरब सागर में बने सिस्टम के कारण 5 दिसंबर तक मौसम साफ होने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर और पूर्वी-पश्चिम अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं। इन सिस्टम के कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला जारी है।

कमलनाथ सरकार बताए, केंद्र से मिले 1000 करोड़ किसानों को क्यों नहीं बांटे : राकेश सिंह

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। कांग्रेस व्कोसेलबाजी कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। वह अपनी गलतियों को केंद्र सरकार पर थोपने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि कर्जमाफ करेगे, आज तक माफ नहीं किया। भारी वर्षा से जो फसलें खराब हुईं, उनका मुआवजा देना तो दूर सर्वे तक नहीं करवाया। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दो बार दल भेजा। इसके पश्चात केंद्र सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए मध्यप्रदेश सरकार को भेजे। मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार किसानों को अभी तक 100 करोड़ रुपए भी नहीं बांट पाईं। यह पैसा प्रशासनिक खर्च चलाने के लिए नहीं, किसानों को देने के लिए दिया गया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि



कांग्रेस ने यह तय किया है कि भाजपा के सांसदों के घरों का घेराव करेंगे। अच्छा किया कि रास्ता खोल दिया। अभी तक हम ऐसा मानते थे कि घरों पर जाकर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है, जिससे हमारे लिए भी रास्ता खुल गया है। सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी भाजपा की सरकार के समय किसानों को कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। अब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सोती रहती है। जब ग्रूरिया की व्यवस्था करना चाहिए, तब आप

टेंडर, तबादले, रेत, शराब के कार्यों में लगे होते हो। जब समय आता है और किसान परेशान होता है, तब ये अपना ठीकरा केंद्र पर थोपने लगते हैं।

एक महिला के लिए घटिया शब्द प्रयोग न करें कांग्रेसी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को इतनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए एक महिला जो साध्वी है, उसके लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल न करें।